THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) The number of rural youth trained under the scheme of TRYSEM during the period 1996-97 and 1997-98, state-wise is given in the Statement. (*See* below)

(b) The number of TRYSEM beneficiaries covered under IRDP is not being monitored separately.

Statement

Number of Youths Trained Under TRYSEM (RE) during the period 1996-97 and 1997-98

S. No.	State/UTs	No. of Youths Trained 1996-97	1997-98*
1.	Andhra Pradesh	83716	14214
2.	Arunachal Pradesh	739	252
3.	Assam	6277	22290
4.	Bihar	34477	24146
5.	Goa	3863	1339
6.	Gujarat	9371	7284
7.	Haryana	3519	1379
8.	Himachal Pradesh	803	545
9.	Jammu & Kashmir	4294	1847
10.	Karnataka	18096	15914
11.	Kerala	5036	3019
12.	Madhya Pradesh	39806	8785
13.	Maharashtra	21447	18234
14.	Manipur	362	766
15.	Meghalaya	352	258
16.	Mizoram	445	370
17.	Nagaland	486	0
18.	Orissa	18555	10354
19.	Punjab	1824	1656
20.	Rajasthan	5766	3179
21.	Sikkim	660	0
22.	Tamilnadu	7687	7280
23.	Tripura	2597	2775
24.	Uttar Pradesh	69272	32662
25.	West Bengal	24199	16088
26.	A&N Islands	486	58
27.	Daman & Diu	75	120
28.	D&N Haveli	107	82
29.	Lakshadweep	12	0
30.	Pondicherry	8	138
	All India	364337	175034

Non-completion of School building in Bihar

853. SHRI NAGENDRA NATH OJHA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a school building of two class rooms, in village Amsari under Dumraon Block of Buxar district of Bihar, was constructed up to the ceiling level under a Centrally sponsored Rojgar Youana and have been left incomplete thereafter; and

(b) if so, the reasons for not completing the construction work and the guidelines issued for completion of the above said school class rooms alongwith details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) and (b) Jawahar Rozgar Youana (JRY) is implemented in a decentraised manner through the Panchayati Raj Institutions (PRIs). Schemes/works are taken up by the PRIs as per the felt need of the people. Activity wise monitoring is not done at central level. However, as per guidelines incomplete works are to be given priority over taking up of new works.

मध्य प्रदेश में कुओं का निर्माण

854. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में दस लाख कुओं के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ मध्य प्रदेश को 1997-98 तक प्रति वर्ष कितनी-कितनी धनराशि दी गई थी तथा उनके निर्माण पर वास्तव में कुल कितनी राशि व्यय हुई:

(ख) राज्य में इस योजना के अंतर्गत निर्मित कुओं की जिला-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) इनमें से सफल और असफल कुओं की जिलावार संख्या कितनी-कितनी है तथा उनके कारण उत्पन्न सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता कितनी है; और

(घ) मध्य प्रदेश विधान सभा की प्राकलन समिति द्वारा इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति, योजना की सफलता तथा अपव्यय आदि के संदर्भ में दिये गये प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटिल): (क) मध्य प्रदेश को दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों का केन्द्रीय

अंश 1996-97 के दौरान 3436.91 लाख रुपए तथा 1997-98 के दौरान 3377.12 लाख रुपए था। 1996-97 के दौरान 3864.57 लाख रुपए तथा 1997-98 के दौरान 3438.96 लाख रुपए खर्च किए गए। 1996-97 से पूर्व दस लाख कुंओं की योजना जवाहर रोजगार योजना की एक उप-योजना थी तथा जवाहर रोजगार योजना के लिए जारी राशि ए का एक भाग दस लाख कुओं की योजना के लिए निर्धारित होता था।

(ख) 1996-97 और 1997-98 के दौरान निर्मित कुंओं के जिले-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए) 1996-97 से पूर्व, निर्मित कुओं के संबंध में जिले-वार जानकारी केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती थी।

(ग) सफल और असफल कुओं तथा उससे प्राप्त सिंचाई की अतिरिक्त क्षिमता संबंधी जानकारी केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(घ) राज्य विधान सभा की, प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट से संबंधित ब्यौरे केन्द्र सरकार स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश में निर्मित कुएं

क्र. सं.	जिला	निर्मित कुंओं की संख्या 1996-97	1997-98	कुल
1.	बालाघाट	381	415	796
2.	बस्तर	1030	650	1680
3.	बेतूल	413	242	655
4.	भिंड	266	103	369
5.	भोपाल	224	38	262
6.	बिलासपुर	1073	822	1895
7.	छतरपुर	609	461	1070
8.	छिंदवाडा	638	287	925
9.	दमोह	221	581	782
10.	दतिया	74	228	302
11.	देवास	188	302	490
12.	धार	470	88	556
13.	दुर्ग	331	262	593
14.	गुना	369	228	597
15.	ग्वालियर	90	30	120
16.	होशंगाबाद	487	751	1238
17.	इंदौर	52	0	52
18.	जबलपुर	465	1024	1489
19.	झाबुआ	441	189	630
20.	खंडवा	622	670	1292
21.	खरगोन	517	490	1407
22.	मंडला	1255	621	1876
23.	मंदसौर	3	0	3
24.	मुरैना	28	241	529
25.	नरसिंह पुर	307	215	522
26.	पन्ना	134	73	207
27.	रायगढ़	980	442	1422
28.	रायपुर	794	882	1676
29.	रायसेन	305	346	651
30.	राजगढ़	79	250	329
31.	राजनंद गांव	379	433	812
32.	रतलाम	158	56	214
33.	रीवा	194	48	242
34.	सागर	738	128	866
35.	सरगुजा	834	1200	2034
36.	सतना	336	351	687
37.	सिहोर	170	292	462
38.	सिवनी	299	134	433
39.	शहडोल	717	444	1161
40.	शाहजापुर	214	89	303
41.	शिवपुरी	132	136	268
42.	सीधी	351	399	750
43.	टीकमगढ़	153	270	423
44.	उज्जैन	234	232	466
45.	विदिशा	243	175	418
	कुल	18658	15296	33954

त्रिमुहानी घाट, बिहार में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण

855. चौधरी हरमोहन सिंह यादव: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत त्रिमुहानी घाट, दरभंगा (बिहार) में अभी तक एक भी मकान नहीं बनाया गया है;

(ख) क्या त्रिमुहानी घाट मकानों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा रखी गई सभी शर्तों को पूरा करता है; और

(ग) यदि हां, तो मकान कब तक बनने की संभावना है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्रऔर रोजगार मंत्रलय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटिल): (क) से (ग) बिहार सरकार से